नईदुनिया

सर्राफा बाजार में उछला सोना, चांदी ने भी लगाई बड़ी छलांग

नई दिल्ली

सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। चेन्नई के अलावा देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना 1,720 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,870 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। वहीं चेन्नई में सोने की कीमत 2,020 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 2,210 रुपये प्रति 10 ग्राम तक बढ़ गई है। इसके अलावा सर्राफा बाजार में हाजिर चांदी ने भी 10,200 रुपये प्रति किलोग्राम तक की छलांग लगाई है।

कीमत में हुए इस बदलाव के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,53,830 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,54,380 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,41,010 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,41,510 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी उछाल आने की वजह से ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में 2,55,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,53,980 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,160 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,53,830 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,41,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,53,880 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,060 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,54,380 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,41,510 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,53,830 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,41,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,880 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,41,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,53,980 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,41,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,53,880 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,41,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,53,980 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,41,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोना शुरुआती कारोबार के दौरान जोरदार उछाल के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,53,830 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 1,41,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

न्यूज ब्रीफ

एलजी के स्वतंत्रता दिवस ऑफर, 26% तक कैशबैक

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने 'ट्रस्ट ऑफ द नेशन' अभियान शुरू किया है। इसके तहत एआई-पावर्ड टीवी, होम अप्लायंसेज और ऑडियो उत्पादों पर आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं। ग्राहकों को चुनिंदा डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 26% तक कैशबैक, अधिकतम 30,000, तथा 888 से शुरू फिक्स्ड ईएमआई का लाभ मिलेगा। चुनिंदा मॉडल पर जीरो डाउन पेमेंट और चुनिंदा एलजी टीवी पर तीन साल की वारंटी भी दी जा रही है। चुनिंदा 4के टीवी के साथ एलजी साउंडबार पर 30% तक छूट और बेस्ट केयर एएमसी पर 20% तक की छूट मिलेगी। कंपनी के अनुसार ये ऑफर सीमित अवधि के लिए एलजी ब्रांड शॉप्स, प्रमुख रिटेल स्टोर और अधिकृत ऑनलाइन चैनलों पर उपलब्ध हैं।

भारतीय व्यापार महोत्सव व्यापारिक इतिहास का मील का पत्थर : खंडेलवाल

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने बुधवार को कहा कि 'भारतीय व्यापार महोत्सव' भारतीय व्यापारिक समुदाय के इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक आयोजित इस 4 दिवसीय व्यापार महोत्सव को संबोधित करते हुए यह आयोजन केवल एक व्यापार प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों व्यापारियों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, निर्माताओं और उद्यमियों को 'वोकल फॉर लोकल' से 'लोकल टू ग्लोबल' की यात्रा से जोड़ने वाला यह एक राष्ट्रीय अभियान है और यह महोत्सव भारत को वैश्विक व्यापारिक शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यूपीआई लेन-देन पर शुल्क का विवाद: उपयोगकर्ताओं के लिए मुफ्त रहेगा लेन-देन

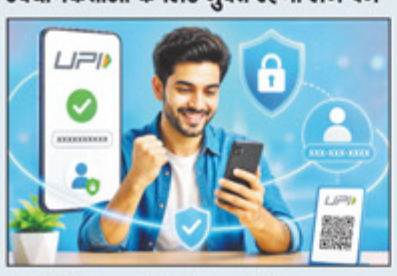

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के बीच, वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए एक विधेयक ने यूपीआई और रुपये पे डेबिट कार्ड लेनदेन पर संभावित शुल्क को लेकर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। इस कदम से सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत ने अमेरिकी दबाव में आकर अपने डिजिटल भुगतान प्रणाली में बदलाव किए हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए लेनदेन पूरी तरह से मुफ्त रहेगा और इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। दरअसल, अमेरिकी सरकार लंबे समय से भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) सिस्टम पर आपत्ति जाहिर करती रही है। अमेरिका ने भारत को उन देशों की सूची में शामिल किया है, जो उसकी वीजा और मास्टरकार्ड जैसी बड़ी पेमेंट कंपनियों के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार कर रहे हैं। इस साल मार्च में, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआरी) ने भारत की डिजिटल भुगतान नीतियों को विदेशी व्यापार में बाधा बताया था, उनका कहना था कि ये नीतियां घरेलू कंपनियों को लाभ पहुंचाती हैं।

टाटा कैपिटल का रिवाल्विंग क्रेडिट एक्सपोजर 5 फीसदी से कम, आरबीआई के नए प्रस्ताव से कंपनी पर पड़ेगा सीमित असर

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को रिवाल्विंग क्रेडिट स्कीम बंद करने के प्रस्ताव से टाटा कैपिटल पर नाम मात्र का असर पड़ेगा। कंपनी ने स्पष्ट किया कि उनके कुल ऋण पोर्टफोलियो में रिवाल्विंग क्रेडिट का हिस्सा 5 फीसदी से भी कम है, जबकि इस कदम से बजाज फाइनेंस जैसी अन्य एनबीएफसी को बड़ी चुनौती मिल सकती है। टाटा कैपिटल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक बैंकिंग सम्मेलन में बताया कि वे आरबीआई के इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देंगे और अंतिम विनियमन का पालन करेंगे। रिवाल्विंग क्रेडिट एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था है जिसमें एक तय सीमा तक बार-बार पैसे उधार लेने और चुकाने की अनुमति होती है। जून के अंत तक टाटा कैपिटल का सकल ऋण 2.86 लाख करोड़ रुपये था। आरबीआई का यह कदम एवरग्रीनिंग के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से है, जहां उधारकर्ता नए ऋण से पुराने ऋण चुकाते हैं। एनबीएफसी की स्व-नियामक संस्था वित्तीय उद्योग विकास परिषद (एफआईडीसी) भी इस सप्ताह इस मुद्दे पर चर्चा करेगी।

एसबीआई को वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में 8 फीसदी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान

मांग, उद्योग और सरकारी खर्च का सहारा, आरबीआई के अनुमान से भी तेज रह सकती है आर्थिक रफ्तार

नई दिल्ली

भारतीय इकोनामी के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई) की एक नई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर लगभग 8 फीसदी रह सकती है। यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 7 फीसदी के अनुमान से काफी अधिक है, जो मजबूत कारोबार, खरीदारी और व्यापक आर्थिक गतिविधियों की ओर इशारा करता है।

एसबीआई की रिपोर्ट बताती है कि अर्थव्यवस्था की यह मजबूती किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। लोगों की खरीदारी और मांग बनी हुई है, औद्योगिक गतिविधियां अच्छी हैं और सेवा क्षेत्र से भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। एसबीआई रिसर्च द्वारा अध्ययन किए गए 54 प्रमुख आर्थिक कारकों में से लगभग 86% में पहली तिमाही के दौरान तेजी देखी गई है, जो पिछले साल की समान अवधि के 69% से काफी अधिक है। यह दर्शाता है कि आर्थिक सुधार सिर्फ एक-दो सेक्टर्स तक सीमित नहीं है। सरकार का विकास परियोजनाओं पर खर्च और बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज में तेजी भी अर्थव्यवस्था को गति दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, कई राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर खर्च जारी है, जो कारोबार और रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। 15 जुलाई 2026 तक बैंकों का कर्ज करीब 17.7 फीसदी की दर से बढ़ा है। इसके अलावा, मानसून में सुधार भी इकोनामी के लिए राहत की खबर है। जून में बारिश में 40 फीसदी की कमी के बावजूद, जुलाई और अगस्त में सामान्य से बेहतर बारिश ने कुल कमी को लगभग 12 फीसदी पर ला दिया है। अच्छी बारिश से खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलता है, जिससे किसानों की आय और गांवों में मांग बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, रिपोर्ट ने रुपये की कमजोरी को लेकर सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। डालर के मुकाबले रुपये का 96 के स्तर को पार कर जाना चिंता का विषय था, हालांकि बाद में इसमें सुधार आया।

अब प्लास्टिक और फ़ाइल में नहीं मिलेगा पान मसाला : एफएसएसएआई

नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। अब पान मसाला को प्लास्टिक, एल्युमीनियम फ़ाइल या मेटलाइज्ड लेयर वाले मटीरियल में पैक नहीं किया जा सकेगा। खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन नियम, 2026 के तहत 10 अगस्त को भारत के राजपत्र में प्रकाशित इन नए प्रावधानों का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित पैकेजिंग सुनिश्चित करना है। नए नियमों के अनुसार पान मसाला को अब अनुसूची 4 में एक नई श्रेणी के रूप में शामिल किया गया है। एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि पान मसाला की पैकेजिंग के लिए कागज, पेपरबोर्ड, सेलुलोज या प्राकृतिक रूप से मिलने वाले अन्य मटीरियल का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते इनमें प्लास्टिक का कोई अंश न हो। इसके तहत पालीइथिलीन, पालीप्रोपाइलीन, पालिएस्टर, पालीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) या कोई अन्य सिंथेटिक पालीमर को-पालीमर या लैमिनेट प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। यहां तक कि कागज की बाहरी परत होने पर भी अंदर प्लास्टिक या मेटलाइज्ड लेयर का उपयोग वर्जित है। विनिर्माताओं के लिए एफएसएसएआई ने टिन या कांच के कंटेनर को भी पैकेजिंग के मंजूर विकल्पों में शामिल किया है। यह संशोधन खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) नियम, 2018 में बदलाव के रूप में आया है। इसके अलावा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के कुछ नियम भी पान मसाला की पैकेजिंग पर लागू होंगे। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। एफएसएसएआई ने इन बदलावों को अंतिम रूप देने से पहले 28 अप्रैल को ड्राफ्ट जारी कर जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे थे, जिन पर विचार करने के बाद ही यह अंतिम अधिसूचना जारी की गई है। यह स्पष्ट किया गया है कि यह नियम पान मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि केवल उनकी पैकेजिंग सामग्री को प्लास्टिक-मुक्त कर पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों की ओर ले जाने पर केंद्रित है।

बैंकिंग में एआई का जिम्मेदारी से करें इस्तेमाल आरबीआई गवर्नर

नई दिल्ली

बैंक के फैसलों की जिम्मेदारी अंततः बैंक की ही होती है, न कि उसके एल्गोरिद्म की

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की नसीहत दी है। एफआईबीएसी 2026 सम्मेलन को संबोधित करते हुए मल्होत्रा ने साफ कहा कि एआई को नियंत्रित किए जाने वाले जोखिम के बजाय एक क्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए जिसका सावधानी से उपयोग हो। साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में आगाह किया कि बैंक के फैसलों की जिम्मेदारी अंततः बैंक की ही होती है, न कि उसके एल्गोरिद्म की।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि ब्रिक्स देशों के सदस्य तेज भुगतान प्रणाली को केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) से जोड़ने पर भी चर्चा कर रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने एआई माडल से जुड़े जोखिमों पर बोलते हुए कहा कि आरबीआई इसे क्षमता के रूप में देखता है। हालांकि, उन्होंने चेताया कि बैंकिंग प्रणाली में एआई अपनाने से मानवीय निर्णय क्षमता और जवाबदेही कम होने का जोखिम हो सकता है।

मल्होत्रा ने जोर दिया, हम यह नहीं कह सकते कि फैसला माडल ने किया। इसमें सार्थक मानवीय निगरानी, फैसले को समझाने और हस्तक्षेप करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने इसे ब्लैक बाक्स समस्या बताते हुए कहा कि एआई सिस्टम के किसी छोटे व्यवसाय को कर्ज न देने की सलाह देने पर, ऋणदाता और नियामक दोनों को कारण जानने का हक है। मल्होत्रा ने एआई में पक्षपात और भेदभाव के जोखिम पर भी आगाह किया, खासकर अगर वह पुराने कर्ज के आंकड़ों पर आधारित हो। उन्होंने थर्ड-पार्टी वेंडर पर निर्भरता और डेटा गोपनीयता के खतरों का भी जिक्र किया, कहा कि ग्राहकों को डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा कानून के पालन से कहीं ज्यादा की उम्मीद करनी चाहिए। आरबीआई गवर्नर ने भारतीय बैंकों को एआई अपनाने में पीछे न रहने पर जोर देते हुए कहा कि वैकल्पिक डेटा जैसे नकदी प्रवाह और जीएसटी फाइलिंग पर प्रशिक्षित एआई माडल ऋण आवंटन की लागत को कम कर सकते हैं।

बैंकों में 2.31 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के फ्रॉड, वसूली केवल 2.7 फीसदी

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों में बड़े वित्तीय फ्रॉड की चिंताजनक तस्वीर पेश की है। वित्तीय वर्ष 2021 से 2026 के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक के कुल 5,607 धोखाधड़ी मामलों में 2,31,710.12 करोड़ रुपए की रकम शामिल थी, जिसमें से महज 6,283.14 करोड़ रुपए की ही वसूली हो पाई। यह दर्शाता है कि 2,25,426.98 करोड़ रुपए की बड़ी राशि अभी भी फंसी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, जहां 2021 से 2024 तक बड़े फ्रॉड के मामलों और राशि में गिरावट देखी गई, वहीं वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 में इनमें तेज उछाल आया। वित्त वर्ष 24 में 641 मामलों के साथ 9,080.50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई, जो छह साल का निचला स्तर था।

सेबी का प्रस्ताव : कमोडिटी डेरिवेटिव में एफपीआई की बढ़ेगी भागीदारी, खुलेंगे नए रास्ते

इन बदलावों से बाजार में तरलता, मूल्य खोज और वैश्विक बाजारों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित होगा

नई दिल्ली

बाजार नियामक सेबी ने एक्सचेंज-ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की भागीदारी बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य गैर-कृषि इंडेक्स डेरिवेटिव्स और नकदी के बिना सेटल होने वाले गैर-कृषि जिंस डेरिवेटिव्स में एफपीआई को व्यापार की अनुमति देना है। सेबी का मानना है कि इन बदलावों से बाजार में तरलता, मूल्य खोज और वैश्विक बाजारों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित होगा। मंगल को जारी अपने परामर्श पत्र में सेबी ने दो प्रमुख प्रस्ताव रखे हैं।

पहले प्रस्ताव के तहत, एफपीआई को अब गैर-कृषि इंडेक्स डेरिवेटिव अनुबंधों में भाग लेने की अनुमति मिलेगी, भले ही इनकी अंतर्निहित संपत्तियां नकदी में सेटल होती हों या नहीं। वर्तमान में, एफपीआई केवल नकदी में सेटल होने वाले गैर-कृषि डेरिवेटिव अनुबंधों में ही निवेश कर सकते हैं।

चूंकि इंडेक्स डेरिवेटिव्स का निपटान हमेशा नकदी में ही होता है, इसलिए यह बदलाव डिलीवरी से जुड़ी कोई समस्या पैदा नहीं करेगा। कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी (सीडीएसी) ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है। दूसरे प्रस्ताव में एफपीआई को घरेलू एक्सचेंजों पर उपलब्ध फिजिकली सेटल होने वाले गैर-कृषि जिंस डेरिवेटिव्स में भी भागीदारी की इजाजत देने की बात कही गई है।

इनमें कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, चांदी और आधार धातु जैसे वैश्विक बेंचमार्क से जुड़े जिंस शामिल हैं। सेबी के अनुसार, इससे बाजार में प्रतिभागियों का आधार और तरलता बढ़ेगी, साथ ही भारत का कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार अंतरराष्ट्रीय जिंस बाजार से गहराई से जुड़ सकेगा। हालांकि, एफपीआई को टेंडर अवधि शुरू होने से पहले (एक्सपायरी से तीन दिन पूर्व) अपने निवेश को बेचना या रोल-ओवर करना होगा। ऐसा न कर पाने पर उनकी खुली पोजीशन स्वचालित रूप से किसी ट्रेडिंग मेंबर के खातों में हस्तांतरित हो जाएंगी।

ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत, एशिया में मिला-जुला कारोबार

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान दबाव में कारोबार करते रहे। डाउ जान्स फ्यूचर्स भी मामूली गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान मिला-जुला कारोबार होता रहा। एशियाई बाजार में भी मिला-जुला कारोबार हो रहा है।

अमेरिका में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन (सीपीआई) यानी महंगाई का आंकड़ा जारी होने वाला है। महंगाई का आंकड़ा आने के पहले अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान निवेशक सतर्क मुद्रा में कारोबार करते रहे। डाउ जान्स इंडस्ट्रियल एवरेज दिन के ऊपरी स्तर से 430 अंक लुढ़क कर 180 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ।

इसी तरह एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 0.32 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 7,728.20 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया।

इसके अलावा नैस्डेक 159.91 अंक यानी 0.60 प्रतिशत टूट कर 26,445.45 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं डाउ जान्स फ्यूचर्स फिलहाल 0.02 प्रतिशत की सांकेतिक कमजोरी के साथ 53,783.16 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के दौरान दबाव में कारोबार करने के बाद मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 0.17 प्रतिशत फिसल कर 10,844.19 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8,714.94 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके विपरीत डीएएक्स इंडेक्स 0.26 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,391.42 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार हो रहा है। एशिया के नौ बाजार में से पांच के सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि तीन सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बने हुए हैं। थाईलैंड के स्टाक एक्सचेंज में छुट्टी होने की वजह से सेट कंपोजिट इंडेक्स में कोई हलचल नहीं हो रही है।

गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 0.03 प्रतिशत की सांकेतिक कमजोरी के साथ 24,508.50 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.40 प्रतिशत लुढ़क कर 5,731.40 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। हैंग सेंग इंडेक्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल यह सूचकांक 290.82 अंक यानी 1.15 प्रतिशत टूट कर 25,362 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

दूसरी ओर, निक्केई इंडेक्स 379.78 अंक यानी 0.56 प्रतिशत की मजबूती के साथ 67,350 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह ताइवान वेटेड इंडेक्स 225.49 अंक यानी 0.50 प्रतिशत उछल कर 45,346.21 अंक के स्तर पर आ गया है। कोस्पी इंडेक्स में जोरदार तेजी नजर आ रही है। फिलहाल यह सूचकांक 282.70 अंक यानी 4.27 प्रतिशत की छलांग लगा कर 6,628.23 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 0.47 प्रतिशत की बढ़त के साथ 6,297.59 अंक के स्तर पर और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.31 प्रतिशत की मजबूती के साथ 3,946.51 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।